ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत,- बाबू जमाल पुर, जिला रोहतक
वीजोगी राम, आदि (सोढ़ी, जे.)

अपीलीय सिविल

*एसबी कपूर और एचआर सोढ़ी से पहले,]*एफ.

ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, बहु जमालपुर, जिला मुख्यालय,—एक अपील

■ *बनाम .* - एफ :

जोग रामएनो*ओटिम्स,-प्रतिवादी'; - . :*

निष्पादन द्वितीय अपील क्रमांक 1414 सन् 1963

■सितंबर 23, 1968

*पंजाब 'ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1*1954)—एस. 3—शर्नीतट भूमि ग्राम पंचायत में निहित है—चाहे धन डिक्री के निष्पादन में बेची जा सकती है या पट्टे पर दी जा सकती है—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V)—एस. 51—पट्टे के माध्यम से अस्थायी हस्तांतरण—क्या निष्पादन न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

*आयोजित,*यह कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट के तहत किसी मनी डिक्री के निष्पादन में, उसमें निहित पंचायत भूमि को पट्टे पर देना किसी कार्यकारी न्यायालय के लिए खुला नहीं है। ज़मीनें एक कॉर्पोरेट निकाय की हैं, जिसके पास निपटान की सीमित शक्तियाँ हैं और उस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किया गया कुछ भी अधिकार से परे होगा। जिन परिस्थितियों में संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए पट्टे दिए जा सकते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में शामिल किया गया है और निष्पादन न्यायालय उन पर हावी नहीं हो सकता है।

(5) एआईआर 1938 दौड़। 38.""-
(6) एआईआर 1943 पटना (24.

प्रावधान. ग्राम पंचायत में निहित भूमि, जिसके विरुद्ध धन डिक्री निष्पादित करने की मांग की गई है, को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अर्थ के तहत पंचायत की निपटान शक्ति के तहत नहीं कहा जा सकता है, ताकि किसी व्यक्ति को भूमि धारण करने में सक्षम बनाया जा सके। पंचायत के खिलाफ धन डिक्री को अपने डिक्री के निष्पादन में बेचने या पट्टे पर देने के लिए।

(पैरा 7)

***आयोजित,*संहिता की धारा 51 डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीकों को बताती है, लेकिन इसे नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। पट्टे के माध्यम से अस्थायी अंतरण एक नहीं हैइस धारा में दिए गए डिक्री के निष्पादन के तरीकों के बारे में। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा का अवशिष्ट खंड (ई) केवल निष्पादन के उन विशेष तरीकों को संदर्भित करता है जो संहिता के आदेश 21 के कुछ नियमों में प्रदान किए गए हैं, उदाहरण के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री या आदेश 21 के तहत निषेधाज्ञा के लिए। नियम 32 और ऐसे अन्य प्रावधान। अस्थायी पट्टे देने का इरादा नहीं हैद्वाराकेवल संहिता की धारा 51 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निष्पादन न्यायालय। (पैरा $ और 6)**

***21 जुलाई को माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. डी. शर्मा द्वारा संदर्भित मामला,*19'66, मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को। मामले का निर्णय अंततः 23 सितंबर, 1968 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एसबी कपूर और माननीय श्री न्यायमूर्ति एचआर सोढ़ी की खंडपीठ द्वारा किया गया।**

श्री कुल भूषण के न्यायालय के आदेश से निष्पादन द्वितीय अपील*, जिला न्यायाधीश, रोहतक, दिनांक 23 सितंबर, 1963, श्री एम के आदेश को पलटते हुए।*एल. जैन, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक, दिनांक*16 नवम्बर, 1962 (*प्रत्याक्षेपों को स्वीकार करते हुए और डिक्री से संतुष्ट न होने पर डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है) और मामले को आदेश में की गई टिप्पणी के आलोक में इसके निपटान के लिए भेज दिया जाता है।

डीसीजीउप्टा और**सपा**जेऐन, एवकालत,***के लिए*अपीलकर्ता।

जीANGAपीअर्शअदजेऐन,और**जी।सी।**जीआर्ग, EDVOCATES,**उत्तरदाताओं के लिए.**

प्रलय

एसओडीएचआई, जे.—यह निष्पादन दूसरी अपील 21 जुलाई, 1966 को पीडी शर्मा, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिनका विचार था कि वर्तमान विवाद में शामिल मुद्दा सार्वजनिक महत्व का है और चूंकि इसके उत्पन्न होने की संभावना है। यह बड़ी संख्या में आसान था। यह अधिक समीचीन है कि इसका निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। इसी सन्दर्भ के कारण अब यह अपील हमारे सामने आई है।

ग्राम सभा.-संलग्न ग्राम पंचायत, बाबू जमाल पुर, जिला रोहतक
इ/जोगी राम, आदि (सोढ़ी, जे.)

(2) तथ्य विवादो में नहीं हैं। जोगी राम और अन्य ने गांव बहु जमालपुर, तहसील और जिला रोहतक की ग्राम पंचायत के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी ग्राम पंचायत को वादी के घरों के सामने सड़क की सतह को बराबर रखने का निर्देश दिया गया। वादी का स्तर^अन्य घर और इस सतह को नीचे न करें। वादीगणों को संभवतः यह आशंका थी कि वे सुविधापूर्वक अपने घरों तक पहुँचने और अपने मवेशियों को वहाँ ले जाने की सुविधा से वंचित हो सकते हैं। उस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि मुकदमा आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था और पक्का तटबंध बनाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उक्त ग्राम पंचायत को कुछ निर्देश दिए गए थे। वादी इन निर्देशों से संतुष्ट नहीं थे और वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष अपील की गई, जिन्होंने आंशिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया और ग्राम पंचायत को योजना पर चिह्नित सड़क को भरने के निर्देश देने की हद तक मुकदमा दायर किया। निश्चित स्तर। ग्राम पंचायत को गोदू राम और टेकु राम के मकानों के किनारे एक फीट चौड़ाई का पक्का तटबंध बनाकर उन मकानों के किनारे एक ज फीट चौड़ाई की पक्की नाली का भी निर्माण करना था। ग्राम पंचायत द्वारा अन्य विवरण भी अनुपालन किए जाने थे और पांच वादी को रुपये का योगदान देना था। इस उद्देश्य के लिए जुटाई जाने वाली सामान्य निधि में से प्रत्येक को 100 रु. दिए गए। डिक्री में यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि ग्राम पंचायत इसका अनुपालन करने में विफल रहती है, अर्थात्, डिक्री में उल्लिखित स्तर तक सड़क को भरने और उसमें शामिल होने के अनुसार पक्की नल्ली और पक्की फर्श बनाने के लिए। वादीगण अपने स्वयं के खर्च पर ऐसा भरने और निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे वे ग्राम पंचायत से वसूलने के हकदार होंगे। अपील में पारित डिक्री की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में की गई। निष्पादन मामले का रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकार का निष्पादन आवेदन किया गया था। पार्टियों के विद्वान वकील यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि निष्पादन न्यायालय ने वादी प्रतिवादियों को देय राशि की गणना की थी या नहीं। लेकिन जैसा भी हो, निष्पादन न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन को ऐसे माना जैसे कि यह पैसे के लिए डिक्री थी, शायद इसलिए क्योंकि वादी डिक्री-धारकों, जो अब प्रतिवादी हैं, ने कुछ राशि का दावा किया था। इस डिक्री के निष्पादन में, ग्राम पंचायत की कुछ भूमि को कुर्क कर लिया गया था, जिस पर बाद में आपत्तियां दायर की गईं कि संपत्ति कुर्की और निष्पादन में बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं थी।

एक धन डिक्री का. पक्षों की दलीलों पर निम्नलिखित मुद्दा तय किया गया-

"क्या विवादित संपत्ति कुर्की के योग्य नहीं है" डिक्री की संतुष्टि में बिक्री।

विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, जो डिक्री का निष्पादन कर रहे थे, ने ग्राम पंचायत (निर्णय-देनदार) की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और निष्पादन के लिए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कुर्की की जाने वाली संपत्ति पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स के तहत ग्राम पंचायत में निहित है। (विनियमन) अधिनियम, 1^4, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि निर्णय-देनदार पंचायत के पास निपटान शक्ति नहीं है। मामले को डिक्री-धारक द्वारा अपील में उठाए जाने के बाद, जिला न्यायाधीश भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम पंचायत के पास अधिनियम के तहत निहित पंचायत भूमि पर निपटान की पूर्ण शक्ति नहीं थी क्योंकि वह इसका निपटान कर सकती थी। इसलिए, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, उन्होंने निष्पादन न्यायालय से सहमति व्यक्त की कि मनी-डिक्री के निष्पादन में ऐसी भूमि को कुर्क या बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन लाहौर उच्च न्यायालय के कुछ फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें से-नहीं उनके निर्णय में उद्धरण दिया गया है/उन्होंने माना कि निष्पादन न्यायालय पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1955 के नियम 4 में दी गई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए धन डिक्री के निष्पादन में भूमि को पट्टे पर दे सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सरदारनी दातार कौर बनाम राम रतन < और अन्य (1) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसे 'हमारे सामने प्रतिवादी डिक्री-धारक' के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किया गया है। विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1900 (1900 का अधिनियम 13) की धारा 16 का संदर्भ दिया गया था, जिसे तब से निरस्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों से पता चलता है कि वर्तमान निष्पादन दूसरी अपील ग्राम

पंचायत के निर्णय-ऋणी द्वारा दायर की गई थी और ■^समाप्ति के लिए एकमात्र प्रश्न जो इस बेंच को भेजा गया है वह यह है कि क्या भूमि जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत में निहित है धन डिक्री के निष्पादन में निष्पादन न्यायालय द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है।

(3) डिक्री धारक के विद्वान वकील श्री गंगा प्रसाद जैन का तर्क यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 एक निष्पादन न्यायालय को डिक्री को किसी भी तरीके से निष्पादित करने की व्यापक शक्तियां देती है, क्योंकि दी गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है। और, अन्य बातों के अलावा, कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी भी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा और चूंकि भूमि पट्टे पर देने की मांग की गई है

(1) आईएलआर (1920) 1 लाख। 192.

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, बाबू जमाल पुर, जिला रोहतक,
वीजोगी राम, आदि (सोढ़ी, जे.)

पंचायत का है, निष्पादन का एक तरीका पट्टे के माध्यम से उसका अस्थायी हस्तांतरण हो सकता है जैसा कि तब किया जा रहा था जब पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1900 लागू था। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में सरदारनी दत्त कौर के मामले पर भरोसा किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 9 और 11 में पंचायत को बिक्री के माध्यम से निपटान की शक्ति दी गई है।

(4) दूसरी ओर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री दलीप चंद गुप्ता ने तर्क दिया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 60 प्रावधानों के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके प्रावधानों के अनुसार केवल निर्णय-देनदार की संपत्ति कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी है। किसी डिक्री के निष्पादन में, जो निर्णय-ऋणी से संबंधित है, इस अर्थ में कि उसके पास उस पर निपटान शक्ति है जिसे वह अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है और पंचायत के पास उस भूमि पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके द्वारा उसमें निहित है अधिनियम का संचालन. उनका कहना है कि मनी डिक्री के निष्पादन में कोई पट्टा या बिक्री नहीं हो सकती है। इस प्रकार निहित भूमि से बना है।

(5) दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि यह एक निष्पादन न्यायालय के लिए खुला नहीं है, एक धन डिक्री के निष्पादन में, उसके तहत निहित पंचायत भूमि को पट्टे पर देने के लिए कार्यवाही करना। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम की योजना और उद्देश्य पूरी तरह से अलग थे और यह केवल एक कृषि जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में स्थायी अलगाव था जो ऐसा सदस्य नहीं था जो निषिद्ध था। अस्थायी अलगाव की अनुमति थी। उक्त अधिनियम की धारा 16 विशेष रूप से किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कृषि भूमि के पट्टे की अनुमति देती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 68 और 72, जिन्हें अब सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 66) की धारा 7 द्वारा हटा दिया गया है, एक डिक्री के निष्पादन में अस्थायी अलगाव को सक्षम बनाती है। कुछ परिस्थितियों। संहिता की धारा 51 डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीकों को बताती है, लेकिन इसे नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी दर पर, पट्टे के माध्यम से अस्थायी हस्तांतरण इस खंड में प्रदान किए गए डिक्री के निष्पादन के तरीकों में से एक नहीं है। उक्त धारा का अवशिष्ट खंड (ई) निम्नलिखित शब्दों में है-

> "51. ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, न्यायालय, डिक्रीधारक के आवेदन पर, डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकता है-
>
> *******
>
> (ई) राहत अनुदान प्राप्तकर्ता की प्रकृति के अनुसार अन्य तरीके से? आवश्यकता हो सकती है:
>
> ******

(6) ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवशिष्ट खंड केवल निष्पादन के उन विशेष तरीकों को संदर्भित करता है जो संहिता के आदेश 21 के कुछ नियमों में प्रदान किए गए हैं, उदाहरण के लिए * वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री या आदेश 21, नियम 32 और ऐसे अन्य के तहत निषेधाज्ञा के लिए। प्रावधान. संहिता की धारा 68 और 72 का निरसन इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है कि धारा 51 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यकारी न्यायालय द्वारा अस्थायी पट्टे दिए जाने का इरादा नहीं है। सरदारुत दातार कौर का मामला डिक्री-धारक के विद्वान वकील द्वारा जिस पर भरोसा किया गया, उसके अपने अजीब तथ्य थे। इसका निर्णय लाहौर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा मुख्य रूप से पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करते हुए किया गया था, जो अस्थायी अलगाव की अनुमति देता था और इसलिए भी क्योंकि यह माना गया था कि संहिता की धारा 72, निरस्त होने के बाद, निहित है कि- न्यायालय अस्थायी अलगाव करने का अधिकार रखता था। संहिता की धारा 51 की व्याख्या में चर्चा में कुछ टिप्पणियाँ थीं, जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी न्यायालय के पास स्वामित्व बनाने वाले अधिकारों के पूरे बंडल को स्थानांतरित करने की शक्ति है, तो निश्चित रूप से उसके पास उन अधिकारों में से कुछ को स्थानांतरित करने की कम शक्ति है, जो अस्थायी अलगाव शामिल

है; लेकिन निर्णय इस तर्क पर आधारित नहीं था बल्कि मुख्य रूप से संहिता की धारा 72 टी>एफ के प्रावधानों पर आधारित था। पूर्ण पीठ के समक्ष यह तर्क उठाया गया कि निष्पादन न्यायालय अकेले ऐसा नहीं कर सकता है और यदि अस्थायी अलगाव किया जाना है तो इसे कलेक्टर द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इसी संदर्भ में इन प्रावधानों की जांच की गई थी।

(7) मौजूदा मामले में, संपत्ति एक कॉर्पोरेट निकाय की है, जिसके पास निपटान की सीमित शक्तियां हैं और उस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किया गया कुछ भी अधिकार से परे होगा। जिन परिस्थितियों में संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए पट्टे दिए जा सकते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में शामिल किया गया है और निष्पादन न्यायालय उन प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है। ग्राम पंचायत में निहित भूमि और जिसके खिलाफ धन डिक्री निष्पादित करने की मांग की गई है, उसे नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अर्थ के तहत पंचायत की निपटान शक्ति के तहत नहीं कहा जा सकता है, ताकि धारण करने वाले व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सके। पंचायत द्वारा अपने डिक्री के निष्पादन में उसे बेचने या पट्टे पर देने के विरुद्ध एक धन डिक्री। ग्राम पंचायत केवल सभा की एक कार्यकारी समिति है जो 1952 के ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय है और केवल उन्हीं का प्रयोग कर सकती है

शक्तियाँ जो उसे अपनी रचना की क़ानून के तहत करने की अनुमति है। अधिनियम की धारा 5 में विशेष रूप से प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित भूमि का उपयोग या निपटान पंचायत द्वारा केवल संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। 1955 के पुराने नियमों का नियम 4, जो पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन जिस पर जिला न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीलामी द्वारा शमिलत भूमि के पट्टे की अनुमति दी गई है, लेकिन यह शक्ति धारा 5 में दी गई मुख्य शर्त के अलावा, पट्टे देने की प्रक्रिया कई शर्तों और प्रतिबंधों से घिरी हुई है कि पट्टा संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए होना चाहिए। उन सभी प्रतिबंधों और शर्तों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम 4, 5 और 6 का अवलोकन यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि निष्पादन न्यायालय संभवतः उन शर्तों का पालन नहीं कर सकता है और न ही उनकी निगरानी कर सकता है। इसी प्रकार, 1964 के नए नियमों का नियम 3 खेती के लिए पट्टे की अनुमति देता है, लेकिन फिर भी कई शर्तें निर्धारित की गई हैं और उन पर काम किया जाना है, जिससे यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य यह नहीं था कि निष्पादन न्यायालय को ऐसे पट्टे देने चाहिए। .

(8) हालाँकि, डिक्री-धारक बिना किसी उपाय के नहीं है। प्रत्येक पंचायत का एक सभा कोष होता है और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 80 में यह प्रावधान है कि इसका उपयोग "इस या किसी अन्य द्वारा पंचायत या उसकी किसी समिति पर लगाए गए कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।" अधिनियमन और पंचायत के अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।" जब पंचायत के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई हो, जिस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। उस पर डिक्री का पालन करने का दायित्व लगाया गया है। ऐसे मामले में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 80 के अनुसार पंचायत पर एक दायित्व लगाया गया है और सभा निधि की डिक्री राशि की वसूली के लिए डिक्री धारक को खुला होना चाहिए। यह धारा कहीं भी पंचायत द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों को केवल उन कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं करती है जो स्वयं अधिनियम द्वारा लगाए गए हैं और इस्तेमाल की गई भाषा काफी व्यापक है जिसमें इसके खिलाफ डिक्री पारित करने से लगाए गए दायित्व भी शामिल होंगे।

(9) उपरोक्त कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है, जिला न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया जाता है और डिक्री-धारक प्रतिवादी के डिक्री के निष्पादन में अपनी संपत्ति के पट्टे के खिलाफ पंचायत द्वारा की गई आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, इस न्यायालय में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एसबी कपूर, जे.-मैं सहमत हूं।

केएसके,

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा